



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2008/श्रावण 29, 1930

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2008/SRAVANA 29, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

(Department of Commerce)

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2008

New Delhi, the 20th August, 2008

सं. 67 (आर.ई.-2008)/2004—2009

No. 67 (RE-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/36/218/26/एम 09/पी सी-5/
ईपीसीजी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार,
एलएड्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर ई-2008) में, निम्नलिखित
संशोधन करते हैं :

F. No. 01/36/218/26/AM 09/Pol V/EPCG-I.—In
exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the
Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of
Foreign Trade hereby makes the following amendments in
Handbook of Procedures, Vol. I (RE-2008):

1. सार्वजनिक सूचना सं. 26 (आर ई-2008)/2004—2009
दिनांक 3 जून, 2008 द्वारा पैराग्राफ 5.11.3 के बाद जोड़े गए पैराग्राफ
को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

1. The following paragraph added after paragraph
5.11.3 vide Public Notice No. 26 (RE-2008)/2004—2009 dated
3rd June, 2008 stands amended to read as under :—

“जब किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया
जाता है, तो ऐसे निर्यात उत्पादों पर रोक/प्रतिबंध लगाने से
पूर्व पहले से जारी ई पी सी जो प्राधिकार पत्रों के संबंध में
निर्यात दायित्व की अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के
रोक/प्रतिबंध की अवधि के बराबर स्वतः ही बढ़ जाएगी
और निर्यातक को रोक/प्रतिबंध की अवधि के लिए औसत
निर्यात दायित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं
होगी।”

“Whenever a ban/restriction is imposed on export
of any product, export obligation period in respect
of EPCG authorizations already issued prior to
imposition of ban/restriction of such export
products, would stand automatically extended for
a period equivalent to the duration of ban/
restriction, without any composition fee and
exporter would not be required to fulfill average
E.O. as well, for the ban/restriction period”.

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

2. This issues in public interest.

आर. एस. गुज्राल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अवर सचिव

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.